Alloting Paraffin Wax to Units Registered after 30-6-86

1209. SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are refusing to allot paraffin wax to the units registered after 30th June, 1986;

(b) what are the reasons for not alloting paraffin wax to the above units; and

(c) whether Government would reconsider its decision to allot paraffin wax to the units registered after 30th June, 1986?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) and (b) As there is a wide gap between the demand and availability of indigenously produced paraffin wax, it was decided to allocate paraffin wax to those units which were registered on or before 30-6-1986 with the Directors of Industries in the various States and Union Territories.

(c) There is no such proposal at present.

1210. *[Transferred to 12th August, 1993]*

Industries Using Gas as a Feed Stock

1211. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of industries are being developed which would use gas as a feed stock;

(b) if so, sector-wise number of such industries and demand for gas; and

(c) the details of steps taken by Government to ensure supply of gas to these industries?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) Yes, Sir.

(b) The approximate sector-wise allocation of gas is as follows (in MMSCMD):—

Sl. No.	Sector	Allocations
1.	Fertilizer	28.71
2.	Power	38.83
3.	Sponge Iron	5.09
4.	Others	11.98
5.	Shrinkage	10.14
	TOTAL:	94.75

(c) The steps being taken include developing new fields, laying of new gas pipelines, augmenting gas pipelines, augmenting gas processing and transportation capacity in the country.

गैस एजेंसियों के संबंध में लंबित पड़े हुए मामले

1212. **श्री राम सिंह राठवा**: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्रों के आधार पर कार्यरत गैस एजेंसियों/खुदरा बिक्री केन्द्रों से संबंधित कितने मामले न्यायालयों में लंबित पड़े हुए हैं, और

(ख) प्रत्येक मामला कब से लंबित पड़ा हुआ है और प्रत्येक एजेंसी अथवा खुदरा बिक्री केन्द्र कब से कार्यरत है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) अ०जा०/अनुसूचित जनजाति के झूठे प्रमाण पत्रों से संबंधित खुदरा बिक्री केन्द्र की आवंटी डीलरशिपों के दो मामले तथा एल पी जी (रसोई गैस) डिस्ट्रीब्यूटरशिप का मामला विभिन्न अदालतों में लंबित पड़े हैं।

(ख) खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप से संबंधित मामले अदालतों में वर्ष 1983 और 1984 से तथा एल पी जी (रसोई गैस) डिस्ट्रीब्यूटरशिप से संबंधित मामला 1991 से लंबित है। खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिपें जुलाई, 1988 एवं नवम्बर, 1988 से तथा एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप जून, 1991 से कार्य कर रही है।

रसोई गैस एजेंसी खोलने हेतु आर्थिक व्यवहार्यता

1213. **चौधरी हरमोहन सिंह**: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या यह सच है कि 20 हजार से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में भी रसोई गैस एजेंसियों को स्थापित नहीं किया गया जहां इसकी बहुत अधिक मांग है और आज जो आर्थिक दृष्टि से भी व्यवहार्य क्षेत्र है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य क्षेत्रों के संबंध में क्या मापदण्ड है?